आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के अन्तर्गत नजरबन्द संसद सदस्य द्वारा डी० डी० ए० को किस्तों का भुगतान

6746. **श्री निहाल सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1976-77 में मीसा के अन्तर्गत नजरबन्दी अनेक संसद सदस्यों को, जो एम० आई० जी० फ्लैटों के लिए डी० डी० ए० की किस्तों का भुगतान नहीं कर सके थे अब ब्याज समेत इन किस्तों का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए मीसा में नजरबन्द रहे संसद सदस्यों को ब्याज रहित किस्तों का भुगतान करने की अनुमति देगी कि वे नजरबन्द रहने के कारण किस्तों का भुगतान करने मे असमर्थ रहे थे ;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी. सी. सेठी) : (क) जी, नहीं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि केवल एक मामले में (नामत: श्री हुकुम चन्द कछवाय, भूतपूर्व संसद सदस्य) एक अभ्यावेदन इस आशय का प्राप्त हुआ था कि मीसा के अन्तर्गत नजरबन्दी के कारण वे प्रारम्भिक जमा की अदायगी नहीं कर सके थे । 15-5-77 तक न तो उन से ब्याज वसूल किया जा रहा है और न ही 15-5-77 तक बाकी किस्तों पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है ।

(ख) मीसा के अन्तर्गत नजरबन्दी की अवधि तथा इसके बाद एक मास तक के लिए ऐसे मामलों मे रिआयत है ।

Conference of State Chief Ministers to discuss Recommendations of A.P.C.

647. SHRI DAULAT SINGHJI JADEJA:
SHRI AMARSINH RATHAWA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether a conference of State Chief Ministers was convened in New Delhi on 27th July, 1980 to discuss the recommendations of the Agricultural Prices Commission on paddy prices for the ensuing Kharif Crop Season;

(b) if so, the details of the discussion held; and

(c) the decision taken by the Conference?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir.

(b) The State Chief Ministers mainly discussed the cost elements of cultivation of agricultural crops and gave their views on the APC's recommendations on the procurement prices for paddy and coarse cereals. The procurement prices suggested by them for 1980-81 marketing season ranged mostly between Rs. 105|- per quintal to Rs. 140|- per quintal for paddy and some Chief Ministers| Ministers suggested Rs. 117|- to Rs. 150|- per quintal for coarse grains.

(c) This Conference was convened to ascertain the views of different State Governments on price policy for kharif cereals and it did not take any decision.

Cash and Fertilizer Subsidy for small farmers in Flood Affected Areas in Gujarat

6748. SHRI DAULATSINHJI JADEJA:
SHRI AMARSINH RATHAWA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Gujarat State has requested the Centre to grant cash and